INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

NEP-2020 के विजन में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना

(Establishment of quality Universities and Colleges in the vision of NEP 2020)

विनोद कुमार

शोध छात्र

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,

जौनपुर (उत्तर प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/02.2023-19379848/IRJHIS2301011

सारांश :

नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100: जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को सम्रग एवं बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। ताकि छात्रों का संपूर्ण एवं सम्रग विकास किया जा सके। भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज बनने की ओर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक युवा भारतीयों के उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक होने की संभावना है। उच्च शिक्षा को ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार बनाना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, इसलिए, व्यक्तिगत रोजगार के लिए अधिक अवसर पैदा करने से कहीं अधिक है।

महत्वपूर्ण शब्द : *नई शिक्षा नीति 2020 का विजन, विश्वविद्यालय*

प्रस्तावना :

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है। जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्त बन पाएंगे।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन

प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहु–विषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। शिक्षा को शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक पहुंचाने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा को पूरा करके स्थिरता को पूरा करने की ओर होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

अध्ययन के उद्देश्य :

नई शिक्षा निति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को एक कुशल बनाने के साथ–साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता हैं, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) के लक्ष्य को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करना।
- देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना।
- NEP–2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को करना।इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाना, ताकि अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

नई शिक्षा नीति–2020 का विजन :

एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। जिससे कि समाज में बदलाव आ सकें। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाएगा। इस नीति के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत भारतीय होने की गर्व की भावना विकसित होगी। इसके अलावा बच्चे ज्ञान, कौशल आदि प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में लाभकारी साबित होगी।

नई शिक्षा नीति 2023 का उद्देश्य :

नेशनल एजुकेशन पालिसी का मुख्य उद्देश्य भारत मैं प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 में सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे संशोधन किए हैं। जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

नेशनल एजुकेशन पालिसी के सिद्धांत :

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना।
- साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना।
- शिक्षा को लचीला बनाना।
- एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना।
- बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना।
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना।
- तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर।
- मूल्यांकन पर जोर देना।
- विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना।
- बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना।

नई शिक्षा नीति के तहत उच्चतर शिक्षा के कुछ आवश्यक घटक :–

सम्रग एवं बहुविषयक शिक्षा :

नई शिक्षा नीति में छात्रों को सम्रग एवं बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। ताकि छात्रों का संपूर्ण एवं सम्रग विकास किया जा सके। जिसके लिए लचीले पाठ्यक्रमों को विकसित किया जाएगा। एग्री कार्यक्रम की अवधि में भी आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे। साथ ही बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा

गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय :

आज के समय में देश की बेरोजगारी दर घटाने के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। ताकि युवाओं का सम्रग विकास किया जा सके। बहु–विषयक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाएगी।

व्यवसायिक शिक्षा :

इस समय देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक कम है। इनमें से 18 से लेकर 24 वर्ष की आयु के लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन अन्य देशों में यह संख्या 50% से 75% तक की है। इसलिए अब नई शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा गया है। हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा को कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। लोगों की इसी धारणा को दूर करने के लिए इस पॉलिसी के माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। सन् 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के द्वारा कम से कम 50% युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है।

संस्थागत पुनगठन एवं समेकन :

इस योजना का एक मुख्य लक्ष्य है यह भी है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को बड़े और बहू विषयक विश्वविद्यालयों कॉलेज आदि में स्थानांतरण करना है।सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य लगभग 3000 या इससे अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों का विकास इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा निष्पक्ष प्रणाली का सहारा लेकर छात्रों का सामाजिक और मानसिक विकास किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा :

छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीपी द्वारा शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को बहु विषयक दृष्टिकोण एवं ज्ञान की आवश्यकता के साथ–साथ अभ्यास भी करवाया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के साथ–साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान, लोकाचार, परंपराओं, जनजाति परंपराओं, के प्रति शिक्षकों को जागरूक भी किया जाएगा।

सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण और छात्रों का सहयोग :

आज के समय में छात्रों को कुछ अन्य क्षमताएं जैसे–फिटनेस, नैतिक मूल्य का आधार एवं अच्छा स्वास्थ्य आदि के बारे में सिखाना भी अत्यधिक आवश्यक है। छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपायुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग होना चाहिए। अब यह सभी चीजें National Education Policy में जोड़ी गई है। जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें।

गुणवत्ता विश्वविद्यालय और कॉलेज :

➢ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई और दूरदर्शी दृष्टि :–

उच्च शिक्षा मानव के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और भारत को विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसा कि इसके संविधान में कल्पना की गई है–एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से जागरूक, सुसंस्कृत और मानवीय राष्ट्र जो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को बनाए रखता है। उच्च शिक्षा राष्ट्र के सतत आजीविका और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज बनने की ओर बढ़ रहा है, अधिक से अधिक युवा

भारतीयों के उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक होने की संभावना है।

21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारशील, सर्वांगीण और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। इसे किसी व्यक्ति को गहन स्तर पर रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए, और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और 21वीं सदी की क्षमताओं को कई विषयों में विकसित करना चाहिए।

समग्र व्यक्तियों के विकास के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि पूर्व–विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर, उच्च शिक्षा को एक प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और कुशल राष्ट्र के विकास को सक्षम बनाना चाहिए जो अपनी समस्याओं का मजबूत समाधान खोज और लागू कर सके।

निष्कर्ष :

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ताकि भारत में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका प्राप्त हो सके। इसके अलावा इस पॉलिसी के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान रखा गया है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारशील, सर्वांगीण और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। इसे किसी व्यक्ति को गहन स्तर पर रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए, और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और 21वीं सदी की क्षमताओं को कई विषयों में विकसित करना चाहिए। उच्च शिक्षा को ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार बनाना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, इसलिए, व्यक्तिगत रोजगार के लिए अधिक अवसर पैदा करने से कहीं अधिक है। यह अधिक जीवंत, सामाजिक रूप से व्यस्त, सहकारी समुदायों और एक खुशहाल, एकजुट, सुसंस्कृत, उत्पादक, नवीन, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र की कुंजी का प्रतिनिधित्व करता है।

सन्दर्भ :

1) ''नई शिक्षा नीतिः पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव''. आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
2) ''नई शिक्षा नीति पर BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले– नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है''. पंजाब केसरी. 29 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
3) ''नई शिक्षा नीति–2020: प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में''. 30 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
4) ''आइए जानें आखिर देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी''. दैनिक जागरण. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

5) Rohatgi, Anubha] laik (2020–08–07). ''Highlights NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi''- Hindustan Times- अभिगमन तिथि 2020–08–08.

6) ''New Education Policy 2020 : 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा''. अमर उजाला. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.

7) ''नई शिक्षा नीति''. नवभारत टाइम्स. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.

8) ''नई शिक्षा नीतिः पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव''. आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

9) ''नई शिक्षा नीति 2020 : स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें''. हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

10) ''नई शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? जानिए–क्या कहते हैं जानकार''. आज तक. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.

International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies
IRJHIS